Vishv UMIYA Foundation | VUF INSTITUTE CIVIL SERVICES

DAILY CURRENT AFFAIRS

IN HINDI

SPECIAL FOR UPSC & GPSC EXAMINATION

DATE : 06-08-25

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Wednesday, 06 Aug, 2025

Edition : International Table of Contents

Page 01 **Syllabus : GS 3 : Disaster Management**	उत्तराखंड में अचानक आई बाढ़ में चार लोगों की मौत
Page 01 **Syllabus : GS 2 : International Relations**	प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत-फिलीपींस संबंध रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर पहुँचे
Page 04 **Syllabus : GS 2 : International Relations**	ट्रंप द्वारा रूसी तेल पर और अधिक अमेरिकी टैरिफ और यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों की धमकी के बीच भारत अपना रुख बदल सकता है
Page 10 **Syllabus : GS 3 : Internal security**	धन शोधन से कैसे निपटा जाना चाहिए?
Page 11 **Syllabus : GS 2 : Governance**	मृतकों की राजनीति: किसे जीने दिया जाए और किसे मरने दिया जाए
Page 08 : Editorial Analysis **Syllabus : GS 2 : Governance**	भारत के कल्याणकारी राज्य का तकनीकी गणित

Page 01 : GS 3 : Disaster Management

5 अगस्त, 2025 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले के धराली कस्बे में विनाशकारी बाढ़ आई, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग लापता हो गए। मूसलाधार बारिश के कारण आई इस बाढ़ ने बुनियादी ढाँचे और पर्यटन पर निर्भर आजीविका को भारी नुकसान पहुँचाया, जिससे हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की नाज़ुक प्रकृति उजागर हुई।

Flash floods in Uttarakhand leave four dead

- Many feared washed away after water from Kheer Ganga river swept through Dharali in Uttarkashi
- Local authorities estimate that around 60-70 people are missing or trapped in the area
- Nine Army personnel feared missing, 20 people rescued in first three hours, Army officer says

Ishita Mishra
NEW DELHI

At least four persons were killed and dozens feared washed away in Uttarkashi district of Uttarakhand after flash floods triggered by torrential rain hit the Kheer Ganga river on Tuesday afternoon.

The floods hit hotels and residential buildings in Dharali town, situated 8,600 feet above sea level, where video footage recorded by residents showed giant waves of water gushing through the area and swallowing everything in their way, including people and homes.

Residents were heard yelling warnings to their acquaintances to run for their lives. The entire market area of the popular tourist town was washed away in minutes, leaving the place looking like a sludge-filled river bed.

At least 25 establishments, including hotels, guest houses, and homes were completely destroyed. A rough estimate by the district administration says that around 60-70 people are missing or might be trapped in the area. As many as nine Army personnel are feared missing, said Lieutenant-Colonel Manish Shrivastava, the Army's Public Relations Officer at Dehradun. Army rescued around 20 people in the first three hours of the rescue operation, he added.

Blink of an eye: A series of images shows floodwater surging downhill and destroying buildings in Dharali town, located 8,600 feet above sea level, in Uttarakhand, on Tuesday. PTI

Heavy losses

Uttarkashi District Magistrate Prashant Arya said that the floods, which hit the town around 1.45 p.m., had caused heavy losses of life and property.

Sources in the Indo-Tibetan Border Police (ITBP) in the area said that 32 people were rescued by different teams.

As many as 120 people were rescued and given first aid till the time of filing this report.

The administration has also set up relief camps for those affected. Hospitals in the area have been asked to reserve a separate wing for the treatment of injured people, and medical teams have been asked to be ready with beds, oxygen, and medicines.

"There has been heavy destruction in the area around the Harshil helipad, another popular tourist spot which also houses an Army and [Indo-Tibetan Border Police] ITBP camp. Teams of State Disaster Response Force, Army and ITBP were immediately rushed to the spot to carry out rescue operations on a war footing," Mr. Arya said.

Given the poor weather conditions and further predictions of heavy rains over the next couple of days, the administration has announced that all schools will be shut on July 6.

Disaster management officials have been asked to use loudspeakers and sirens to alert people living in villages near the river, in the Chilyanisaur, Bhatwari, and Dunda blocks, asking them to evacuate their homes for safer locations. Trekking permits in Uttarkashi have also been denied until further notice.

CM condoles losses

Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami condoled the losses and ordered the administration to ensure speedy rescue and rehabilitation. "I am in constant contact with senior officials, and the situation is being closely monitored. I pray to God for everyone's safety," the CM said.

Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah also spoke to Mr. Dhami and took stock of the situation and the rescue operation. The Union government has assured the State of its help in the rescue efforts.

Hours after Dharali, information of flash floods triggered by rains was recieved from Sukhi top, another tourists destination in Uttarkashi, said Vinay Shankar Pandey, divisional commissioner of Garhwal region. He added that no loss of life was reported from the spot but the water level in the river increased drastically.

आपदा के कारण

1. अत्यधिक वर्षा की घटनाएँ:

- इसका तात्कालिक कारण बादल फटने जैसी मूसलाधार बारिश थी, जो मानसून की परिवर्तनशीलता और जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय में बार-बार होने वाली घटना है।

2. स्थलाकृतिक और भूवैज्ञानिक भेद्यता:

- उत्तरकाशी 8,600 फीट की ऊँचाई पर स्थित है, जिसकी ढलानें तीव्र हैं और भू-आकृति नाजुक है, जिससे यह भूस्खलन और अचानक बाढ़ के लिए अत्यधिक संवेदनशील है।
- खीर गंगा नदी, जो तेज़ी से उफान पर आने वाली एक सहायक नदी है, उफान पर आ गई और शहर से होकर बह गई।

3. अनियमित पर्यटन और निर्माण:

- o धराली शहर एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जहाँ नदी के किनारों और अस्थिर ढलानों पर कई होटल और गेस्ट हाउस बने हैं।
- o बेतरतीब निर्माण ने विनाश के पैमाने को और बढ़ा दिया।

4. जलवायु परिवर्तन:

- o कम अवधि में उच्च-तीव्रता वाली वर्षा की बढ़ती आवृत्ति हिमालयी क्षेत्र में बदलते जलवायु पैटर्न की स्पष्ट अभिव्यक्ति है।

प्रभाव

मानवीय क्षति:

- o कम से कम 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई; 9 सैन्यकर्मियों सहित 60-70 लोग लापता हैं।
- o 120 से ज़्यादा लोगों को बचाया गया; अस्पतालों को आपातकालीन चिकित्सा देखभाल के लिए तैयार किया गया।

- **बुनियादी ढाँचे का विनाश:**
  - o 25 से ज़्यादा होटल, गेस्टहाउस और घर नष्ट हो गए।
  - o सड़कें, बाज़ार और स्थानीय संचार लाइनें प्रभावित हुईं।

- **विस्थापन:**
  - o राहत शिविर स्थापित किए गए; स्कूल बंद; ट्रैकिंग परमिट रद्द।
  - o आस-पास के गाँवों से लोगों को निकालने के आदेश।

- **राष्ट्रीय प्रतिक्रिया:**
  - o सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ की टीमें युद्धस्तर पर तैनात।
  - o प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मुख्यमंत्री के संपर्क में; केंद्र ने सहायता का आश्वासन दिया।

प्रशासनिक और नीतिगत चुनौतियाँ

- **आपदा तैयारी में खामियाँ:**
  - o दूरदराज के उच्च-ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पूर्व चेतावनी प्रणालियों का अभाव।
  - o मानसून-पूर्व भेद्यता मानचित्रण का अपर्याप्त होना।

- **नीति कार्यान्वयन की कमज़ोरी:**
  - o पारिस्थितिक-संवेदनशील क्षेत्र (ईएसज़ेड) दिशानिर्देशों का उल्लंघन।
  - o संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण मानदंडों का अपर्याप्त प्रवर्तन।

आगे की राह

1. पूर्व चेतावनी प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना:

- ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में स्वचालित वर्षा और बाढ़ निगरानी केंद्रों की स्थापना।

2. सतत पर्यटन और क्षेत्रीयकरण कानून:

- सख्त भवन संहिताओं को लागू करना।
- पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में क्षमता-आधारित पर्यटन योजना बनाना।

3. जलग्रहण और नदी प्रबंधन:

- नदी तल का क्षेत्रीयकरण और तटबंधों को सुदृढ़ बनाना।
- गाद निकालना और जल निकासी व्यवस्था में सुधार।

4. समुदाय-आधारित आपदा तैयारी:

- स्थानीय स्तर पर मॉक ड्रिल, जागरूकता अभियान।
- युवाओं को बचाव और प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण।

5. जलवायु अनुकूलन योजना:

- राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं (एसडीएमपी) में जलवायु जोखिम मूल्यांकन को एकीकृत करना।
- वनरोपण और ढलान स्थिरीकरण जैसे प्रकृति-आधारित समाधानों को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

- उत्तरकाशी में आई अचानक आई बाढ़ ने एक बार फिर हिमालय के विकास के लिए एक समग्र और जलवायु-अनुकूल दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित किया है। चूंकि भारत का लक्ष्य पारिस्थितिक संरक्षण और आर्थिक प्रगति के बीच संतुलन बनाना है, इसलिए ऐसी आपदाओं से प्राप्त सबक को टिकाऊ नीति डिजाइन, सामुदायिक भागीदारी और आपदा तैयारी में शामिल किया जाना चाहिए।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: हिमालयी क्षेत्र में अचानक आने वाली बाढ़ें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसे किस हद तक जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है**?** हाल की घटनाओं के संदर्भ में परीक्षण कीजिए और नीतिगत हस्तक्षेप सुझाइए। **(150 Words)**

Page 01 : GS 2 : International Relations

फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर की भारत यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जिसमें रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया।

प्रमुख घटनाक्रम:

1. रणनीतिक साझेदारी को औपचारिक रूप दिया गया:

- भारत और फिलीपींस ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी से रणनीतिक साझेदारी में उन्नत किया।
- इस उन्नयन को लागू करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है।

2. समुद्री एवं रक्षा सहयोग:

- भारतीय नौसैनिक जहाजों ने पहली बार फिलीपींस में समुद्री अभ्यास में भाग लिया।
- सशस्त्र बलों (थल सेना, नौसेना, वायु सेना) के बीच विचारार्थ विषयों को अंतिम रूप दिया गया।
- भारतीय तटरक्षक बल - फिलीपींस तटरक्षक बल के बीच सहयोग बढ़ाया गया।
- क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण आदान-प्रदान, संयुक्त समुद्री गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

3. दक्षिण चीन सागर और हिंद-प्रशांत:

- भारत ने नौवहन की स्वतंत्रता और नियम-आधारित व्यवस्था के प्रति समर्थन की पुष्टि की।
- कानूनी आधार के रूप में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (यूएनसीएलओएस) 1982 पर प्रकाश डाला।
- दक्षिण चीन सागर को वैश्विक साझा संसाधन के रूप में भारत द्वारा महत्व दिया जाना सीधे तौर पर आसियान की केंद्रीयता को पुष्ट करता है।

India-Philippines relations elevated to level of strategic partnership, says PM Modi

Kallol Bhattacherjee
NEW DELHI

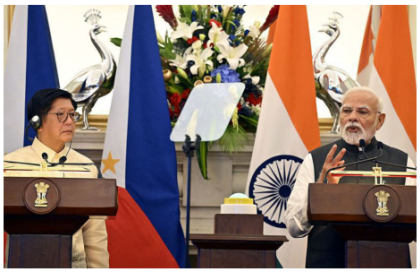

Prime Minister Narendra Modi with Filipino President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. in New Delhi on Tuesday. SHIV KUMAR PUSHPAKAR

India and the Philippines have decided to boost their defence and maritime links, begin direct flights, and start negotiating a new trade deal as they upgrade their ties to the level of a "strategic partnership", Prime Minister Narendra Modi said on Tuesday.

Welcoming visiting Filipino President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Mr. Modi said that as both countries support "freedom of navigation", cooperation in the maritime domain is "natural and essential." The two sides also announced the commencement of talks for a preferential trade agreement.

"We have been consistently working together in areas such as humanitarian assistance, disaster relief, and search and rescue operations. Today, as the President is visiting India, three Indian naval ships are, for the very first time, participating in a naval exercise in the Philippines. India's hydrography ship is also a part of this important engagement," the Prime Minister said. He also expressed his "sincere gratitude" to the government of the Philippines for condemning the terror attack in Pahalgam on April 22.

The Prime Minister discussed regional and global issues with the Filipino President, and hinted at India's position on the disputes in the South China Sea.

"We remain committed to peace, security, prosperity, and a rules-based order in the Indo-Pacific region. We support freedom of navigation in accordance with international law," he said.

Mr. Modi described the Philippines as an "important partner" in India's Act East Policy. "I am happy to share that we have decided to upgrade our ties to a strategic partnership. We have also prepared a detailed action plan to turn this partnership's potential into outcomes," he said. The Prime Minister also announced that direct flights between India and the Philippines will begin this year, while India will extend a free e-tourist visa facility to Filipino nationals for a period of one year, starting August 2025.

Defence cooperation

The two countries agreed on a number of defence-related mechanisms including the finalisation of the Terms of Reference between their armies, navies and air forces.

These agreements will cover "capacity building, joint maritime activities, exchange of training programmes between our officials, and all standard elements when we talk about defence cooperation", according to P. Kumaran, Secretary (East) of the Ministry of External Affairs. The two countries also agreed on the Terms of Reference for enhanced maritime cooperation between the Indian Coast Guard and the Philippine Coast Guard.

Mr. Kumaran also reiterated India's position on the South China Sea. "We consider the South China Sea as a part of the global commons. We support freedom of navigation and overflight in the region, and legitimate commerce through the waters of the South China Sea. India has an abiding interest in peace and stability in the region and our position is based on the UN Convention of the Law of the Seas, 1982," he said.

India and the Philippines sealed a treaty on mutual legal assistance in criminal matters and another treaty on the transfer of sentenced persons.

India announced that it will extend its support to a pilot project to set up the infrastructure needed for the Philippines Sovereign Data Cloud. India also invited the Philippines to participate in its Information Fusion Centre for the Indian Ocean Region.

4. आर्थिक सहयोग:

- o एक अधिमान्य व्यापार समझौते (PTA) के लिए बातचीत की शुरुआत।
- o भारत फिलीपींस में एक पायलट सॉवरेन डेटा क्लाउड परियोजना का समर्थन करेगा।
- o पारस्परिक कानूनी सहायता संधि और सजायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण पर संधि पर हस्ताक्षर किए गए।

5. संपर्क और लोगों के बीच संबंध:

- o भारत और फिलीपींस के बीच सीधी उड़ानें 2025 में शुरू होंगी।
- o अगस्त 2025 से फिलीपींस के नागरिकों के लिए मुफ्त ई-पर्यटक वीजा।

भारत और उसके पड़ोसी एवं सामरिक हित:

- आसियान देशों के साथ संबंधों को गहरा करना भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण के अनुरूप है।
- फिलीपींस जैसे प्रभावित आसियान देशों के साथ संबंधों को मजबूत करके दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता का मुकाबला करना।

आलोचनात्मक विश्लेषण:

महत्व:

- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की छवि को मज़बूत करता है।
- द्विपक्षीय रक्षा संबंधों में रणनीतिक गहराई जोड़ता है।
- संभावित पीटीए और डिजिटल अवसंरचना परियोजनाओं के माध्यम से आर्थिक अवसर खोलता है।

चुनौतियाँ:

- क्षेत्र में भारत के गहरे रक्षा संबंधों के प्रति चीन की प्रतिक्रिया प्रतिकूल हो सकती है।
- व्यापार समझौतों और रक्षा सहयोग के कार्यान्वयन के लिए निरंतर राजनीतिक और नौकरशाही इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: भारत की एक्ट ईस्ट नीति उत्तरोत्तर रणनीतिक प्रकृति की होती जा रही है। भारत-फिलीपींस संबंधों के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

Page : 04 : GS 2 : International Relations

भारत की विदेश नीति और ऊर्जा सुरक्षा रणनीति एक नई भू-राजनीतिक चुनौती का सामना कर रही है क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प के संभावित राष्ट्रपतित्व में, संयुक्त राज्य अमेरिका दंडात्मक शुल्क लगाने की धमकी दे रहा है और यूरोपीय संघ भारत द्वारा रूसी तेल के निरंतर आयात पर प्रतिबंध लगा रहा है। यह घटनाक्रम एक महत्वपूर्ण मोड़ है जहाँ नई दिल्ली अपने पारंपरिक रुख को बदलकर राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए दृढ़ कूटनीतिक और आर्थिक विकल्प तलाश सकता है।

India may change stance amid Trump's threat of more U.S. tariffs, European Union sanctions over Russian oil

NEWS ANALYSIS

Suhasini Haidar
NEW DELHI

Weighing options: India could continue to buy crude from Russia or seek alternative partners. FILE PHOTO

The statement by the Ministry of External Affairs on Monday, defending India's purchases of Russian oil, is its most explicit since Russia's invasion of Ukraine in 2022, making it clear that India will take "all necessary measures" to safeguard its interests.

The MEA's response followed the new threats by U.S. President Donald Trump to impose penalty tariffs over and above the massive 25% reciprocal tariffs the U.S. will impose on Indian goods as tariffs kick in worldwide on Thursday. It also followed EU sanctions imposed in July against Rosneft's partially-owned Vadinar refinery and other Indian companies engaged in reprocessing Russian oil.

On Monday, Mr. Trump said India was selling "massive amounts" of Russian oil for "big profits" without "caring how many people in Ukraine are being killed by the Russian war machine", which was why he would raise tariffs "substantially". The MEA statement called out both the U.S. and the European Union for their double standard, given they themselves continued to purchase Russian energy, critical minerals, fertilizers, iron and steel.

India shifted its oil purchases to Russia after 2022, when Ural imports made up less than a per cent of its oil imports, increasing to as much as 40% by 2023. However, the MEA statement said that India's purchases are "compelled" by the global market and the need for affordable energy costs. It added that in comparison the U.S. and EU imports from Russia were not even a "vital national compulsion", calling the targeting of India "unjustified and unreasonable".

The statement left other double standard unsaid, such as the U.S. and Europe's funding and arming Israel's war in Gaza, that has led to the killing of at least 60,000 Palestinians, including 18,000 children. Nor did it point out that the U.S. has not announced penalties on China, a bigger buyer of Russian oil. Meanwhile, Mr. Trump himself, just a few months ago was much less critical of the Russian war, and had even threatened Ukrainian President Volodymyr directly for not engaging with Russia. "Like any major economy, India will take all necessary measures to safeguard its national interests and economic security," said the MEA.

This marks a shift from the past when New Delhi's response to low-impact U.S. and EU sanctions of Indian companies for Russian transactions was submissive. In 2017, the Modi government agreed to "zero out" all its oil imports from Iran and Venezuela, even though they were cheaper and of higher quality, after threats from the previous Trump administration. In 2022, India refused to submit to threats from the Biden administration, possibly as it did not believe it would carry out those threats, as Mr. Trump is quite clearly capable of doing.

Changing tack

The MEA's statement could indicate that it is prepared to change to a third tack – that of considering "measures" against any further costs imposed by the West, even though Indian oil companies have begun reducing their Russian intake. These measures, according to experts could be three-fold: maintaining *status quo*, looking for alternative partners, and retaliatory actions.

The first option would be to continue to buy Russian energy at competitive prices and even double down on them, while weathering sanctions imposed by the U.S. and the EU, and continuing to pursue free trade agreements with both in the hope these would lessen such penalties. This is the strategy that the government has employed thus far.

The next option, to search for alternative options for trading to circumvent U.S.-EU sanctions, could include moving to quickly conclude FTA negotiations ongoing with the GCC, EAEU, Australia, New Zealand, and so on. It could also conclude talks on revising the ASEAN-India Trade in Goods Agreement or even a re-look at joining the 15-nation ASEAN-led Regional Comprehensive Economic Partnership that India withdrew from in 2019, largely due to concerns about China. While this was not a possibility even a few weeks ago, when Commerce and Industries Minister Piyush Goyal referred to ASEAN as the "B-team of China", and the AITIGA as a "mistake", the government's outlook may change given Mr. Trump's relentless tirades.

The third option, of countermeasures, could involve suspending talks with the EU on the BTIA, and with the U.S. on trade, nuclear energy, defence purchases and others until they prove more reasonable on the issue.

India could also consider restarting Iran and Venezuela oil supplies, which could prove cost-effective, but could also incur further sanctions. Experts also point out that the Russian penalties are only one of a barrage of actions by Washington that may lead New Delhi to reconsider its ties with the U.S. in other spheres as well – with divergences emerging on trade and investment, repercussions on technology transfer, counter-terrorism strategy (given Mr. Trump's moves with Pakistan and counter-narrative on Operation Sindoor), and multilateralism with Mr. Trump's threats against BRICS. All eyes are now on whether the turbulence will impact the strongest pillar of India-U.S. ties – their shared Indo-Pacific strategy and the Quad summit that India is due to host this year.

पृष्ठभूमि और संदर्भ

2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से, भारत ने सामर्थ्य के कारण रूस से अपने कच्चे तेल के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि की है। 2023 तक, रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया, जिसने इराक और सऊदी अरब जैसे पारंपरिक साझेदारों की जगह ले ली। हालाँकि, इन आयातों की पश्चिमी देशों से आलोचना और जवाबी कार्रवाई हुई है, जिनमें शामिल हैं:

- रूसी तेल पुनर्संसाधन से जुड़ी भारतीय संस्थाओं पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंध।
- डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारतीय वस्तुओं पर भारी शुल्क लगाने की चेतावनी, जिसमें भारत पर युद्ध से मुनाफाखोरी का आरोप लगाया गया।
- जवाब में, भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने अपने संप्रभु ऊर्जा विकल्पों का बचाव करते हुए एक कड़ा बयान जारी किया, जो अमेरिकी दबावों के प्रति पहले के विनम्र रुख से हटने का संकेत देता है।

भारत की रणनीतिक दुविधा

भारत अब तीन संभावित रणनीतिक प्रतिक्रियाओं के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है:

1. यथास्थिति बनाए रखें

- **रियायती दरों पर रूसी ऊर्जा आयात जारी रखें।**
- अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ चल रही मुक्त व्यापार समझौते (FTA) वार्ताओं को आगे बढ़ाएँ, इस उम्मीद में कि व्यापार कूटनीति प्रतिबंधों को कम कर सकती है।
- उदाहरण: 2022 के बाद भारत का पूर्व दृष्टिकोण गुटनिरपेक्षता को रणनीतिक चुप्पी के साथ संतुलित करता था।
- चुनौतियाँ: बढ़ते वित्तीय और तकनीकी प्रतिबंधों और बातचीत की गुंजाइश कम होने का सामना करना पड़ सकता है।

2. वैकल्पिक साझेदारों की तलाश करें

- जीसीसी, ईएईयू, ऑस्ट्रेलिया और आसियान के साथ व्यापार और ऊर्जा साझेदारी में तेज़ी लाएँ।
- चीन को लेकर चिंताओं के कारण पहले वापसी के बावजूद, आरसीईपी में शामिल होने पर पुनर्विचार करें।
- ईरान और वेनेजुएला, जो सस्ता कच्चा तेल उपलब्ध कराते हैं, के साथ नए द्विपक्षीय और क्षेत्रीय ऊर्जा समझौतों की संभावनाएँ तलाशें।
- अर्थ: यह रास्ता ऊर्जा स्रोतों में विविधता ला सकता है और किसी भी समूह पर अत्यधिक निर्भरता को कम कर सकता है, लेकिन इसके साथ कूटनीतिक संतुलन की चुनौतियाँ भी जुड़ी हैं।

3. जवाबी कार्रवाई

- भारत-यूरोपीय संघ बीटीआईए पर बातचीत स्थगित करें और अमेरिका के साथ उच्च-स्तरीय व्यापार वार्ता स्थगित करें।
- क्वाड जैसे रणनीतिक संवादों में भागीदारी पर पुनर्विचार करें या अमेरिका से रक्षा खरीद में देरी करें।
- ईरान और वेनेजुएला से तेल आयात बहाल करें, भले ही द्वितीयक प्रतिबंधों का जोखिम हो।
- महत्व: यह संप्रभु दृढ़ता को दर्शाता है, लेकिन रणनीतिक गठबंधनों में विश्वास को कम कर सकता है।

भू-राजनीतिक अंतर्धाराएँ और दोहरे मानदंड

- भारत ने पश्चिमी पाखंड को भी उजागर किया है - जहाँ यूरोपीय संघ और अमेरिका भारतीय आयातों की आलोचना करते हैं, वहीं वे स्वयं रूसी गैस, खनिज और धातुएँ खरीदना जारी रखते हैं। इसके अलावा, अमेरिका ने रूसी कच्चे तेल के एक प्रमुख आयातक चीन पर प्रतिबंध नहीं लगाए हैं, जो भारत को चुनिंदा रूप से निशाना बनाने का संकेत देता है।
- यह भी उल्लेखनीय है कि गाजा में इज़राइल के युद्ध को अमेरिका द्वारा समर्थन दिए जाने पर चुप्पी साधे रखी गई है, जिससे भारी नागरिक हताहत हुए हैं, जिससे नैतिक स्थिरता पर सवाल उठ रहे हैं।

भारत की विदेश नीति के व्यापक निहितार्थ

- ऊर्जा सुरक्षा: भारत का आयात बढ़ती अर्थव्यवस्था की कीमत और मात्रा संबंधी आवश्यकताओं से प्रेरित है, न कि राजनीति से।
- सामरिक स्वायत्तता: दबाव के आगे झुकने से भारत का इनकार एक वैश्विक शक्ति के रूप में उसके बढ़ते आत्मविश्वास को दर्शाता है।
- अमेरिका-भारत संबंध: मज़बूत होते हुए भी, ट्रम्प की अनिश्चितता रक्षा, प्रौद्योगिकी और क्वाड शिखर सम्मेलन सहित हिंद-प्रशांत सहयोग की परीक्षा ले सकती है।
- बहुपक्षवाद: यदि पश्चिमी दबाव बढ़ता है, तो भारत ब्रिक्स जैसे मंचों पर अपनी भूमिका को नए सिरे से निर्धारित कर सकता है।

निष्कर्ष

- भारत का बदलता रुख व्यावहारिक राजनीति की ओर बदलाव का संकेत देता है - जहाँ राष्ट्रीय हित मानक संरेखण पर हावी हो जाता है। जैसे-जैसे युद्ध, प्रतिबंधों और रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बीच वैश्विक व्यवस्था पुनर्गठित होती है, तेल कूटनीति में भारत की संतुलित दृढ़ता आर्थिक सुरक्षा और वैश्विक अपेक्षाओं के बीच संतुलन बनाने वाली मध्यम शक्तियों के लिए एक आदर्श के रूप में उभर सकती है। आने वाले महीने महत्वपूर्ण साझेदारियों का त्याग किए बिना रणनीतिक स्वायत्तता का दावा करने की भारत की क्षमता का परीक्षण करेंगे।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच भारत की तेल कूटनीति रणनीतिक स्वायत्तता की ओर बदलाव को दर्शाती है। अमेरिका और यूरोपीय संघ के बढ़ते भू-राजनीतिक और आर्थिक दबाव के संदर्भ में भारत की उभरती ऊर्जा नीति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। **(150 Words)**

Page 10 : GS 3 : Internal security

अवैध रूप से अर्जित धन को वैध संपत्ति में बदलने की प्रक्रिया, मनी लॉन्ड्रिंग, भारत की वित्तीय अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। वित्त मंत्रालय की राज्यसभा को दी गई हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 2015 से अब तक धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 5,892 मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन केवल 15 मामलों में ही दोषसिद्धि हो पाई है। यह बड़ा अंतर भारत में वित्तीय अपराधों से संबंधित प्रवर्तन और न्यायिक प्रक्रियाओं में गंभीर चुनौतियों को दर्शाता है।

How should money laundering be tackled?

What did the Finance Minister report with respect to the number of cases under the Prevention of Money Laundering Act? What are the three stages through which money is laundered? How will the Double Taxation Avoidance Agreement help to stop illegal transfer of money?

EXPLAINER

C. B. P. Srivastava

The story so far:

A report submitted by the Finance Minister in the Rajya Sabha states that 5,892 cases were taken up by the Enforcement Directorate (ED) under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) 2002, since 2015. Of these cases, only 15 convictions have yet been ordered by special courts. The government claims that investigations have been initiated in more or less all cases, and that Enforcement Case Information Reports (ECIRs) have been issued to initiate proceedings. However, these figures raise two important aspects. First, that the number of convictions vis-a-vis total cases is far from satisfactory and secondly, that money laundering cases have been rising signalling that the government has not been able to check such financial crimes.

What is a laundromat?

The term is said to have originated from the use of laundromats by organised crime syndicates in the U.S. as cover for their crimes and under-the-table dealings. A laundromat is an all-purpose financial vehicle. It may be set up by a bank or any other company engaged in providing financial services. However, it can also help clients launder the proceeds of crime, hide ownership of assets, embezzle funds from companies, evade taxes or currency restrictions and move money offshore.

How is money laundered?

Money laundering, as defined under Section 3 of PMLA, is an act through which processes or activities connected to the proceeds of crime are concealed, possessed, acquired, or used and projected as untainted property or claiming to be untainted property.

In the first stage called placement, the launderer introduces money into the financial system which might be done by breaking up large amounts of cash into smaller sums (a process called smurfing). In the second stage, that is layering, money is shifted to other locations through investments and transactions. And finally in the integration stage, the laundered money is brought into the financial system through real estate, business or asset formation etc. The Supreme Court in *P. Chidambaram versus Enforcement Directorate* (2019) held that hiding the illegal source of money affects the financial system and also the sovereignty and integrity of the nation. Other impacts of money laundering include expansion of money supply which might prove detrimental to monetary stability of the country ultimately impacting inflation. Moreover, it may also affect trading, according to the Financial Action Task Force (FATF).

ISTOCKPHOTO

When about the PMLA?

In line with the UN Political Declaration and Global Programme of Action (adopted by the UN General Assembly in February 1990), the law has been made to prevent money laundering and to confiscate the property involved or obtained. The most significant part of the statute is that the burden of proof is on the accused. Another feature is that the ECIR is sufficient to initiate proceedings which has also been reiterated by the Supreme Court in *Vir Bhadra Singh versus ED* (2017) – that no FIR is required to initiate proceedings under the Act. The only requirement as per the top court was that a scheduled offence (offence against the state) be essential for the offence of money laundering. However, despite being such a stringent law, the offence has become rampant.

What are the issues to be addressed?

The number of money laundering cases is seriously increasing, questioning the efficacy of the implementation of the law. Moreover, on many occasions, the law has been abused by authority which has been seen and referred to by the Supreme Court as well. In *Vijay Madanlal Chaudhury versus Union of India* (2022) the Court held that to initiate prosecution under Section 3 of the PMLA, registration as scheduled offence is a pre requisite but for initiating attachment of property under Section 5, there need not be a pre-registered criminal case. This view has been very often misused by authorities with politically motivated intentions.

It is important that the authorities follow the recommendations of the FATF and ensure that money laundering cases are handled with care and caution so that misuse could be checked, and genuine cases reported and investigated properly to enhance the rate of conviction. Money laundering is a serious offence as it has a direct linkage with terror activities and is a major source of terror financing. Instead of political motives, the law should be used to address the issues and concerns involved in a genuine manner. Though India has signed the Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) with about 85 countries, which helps to check money laundering, things are not yet in the right direction and much needs to be done. These agreements promote the exchange of financial and tax-related information between tax authorities of participating countries. This facilitates the enforcement of tax regulations and helps prevent illegal activities like tax evasion and money laundering.

C. B. P. Srivastava is President of the Centre for Applied Research in Governance.

THE GIST

- Money laundering, as defined under Section 3 of PMLA, is an act through which processes or activities connected to the proceeds of crime are concealed, possessed, acquired, or used and projected as untainted property or claiming to be untainted property.
- The number of money laundering cases is seriously increasing, questioning the efficacy of the implementation of the law.
- Though India has signed the Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) with about 85 countries, which helps to check money laundering, things are not yet in the right direction and much needs to be done.

प्रक्रिया और चुनौतियों को समझना

धन शोधन के चरण

- **पीएमएलए के अनुसार, इस प्रक्रिया में तीन चरण शामिल हैं:**

1. प्लेसमेंट - वित्तीय प्रणाली में अवैध धन का प्रवेश।

2. लेयरिंग - मूल स्रोत को छिपाने के लिए विभिन्न खातों और लेनदेन के माध्यम से धन का स्थानांतरण।

3. एकीकरण - वैध संपत्ति (जैसे, अचल संपत्ति या व्यवसाय के माध्यम से) के रूप में धन शोधन को अर्थव्यवस्था में पुनः प्रवेश।

धन शोधन से निपटने में समस्याएँ

- कम दोषसिद्धि दर: हजारों जाँचों के बावजूद, दोषसिद्धि दर बेहद कम बनी हुई है।
- कानून का दुरुपयोग: अदालतों ने पीएमएलए के राजनीतिक रूप से प्रेरित कार्यों के लिए दुरुपयोग के मामलों को चिह्नित किया है, विशेष रूप से अनुसूचित अपराध के अभाव में।
- प्रक्रियात्मक अस्पष्टता: सामान्य आपराधिक कानून में एफआईआर के विपरीत, पीएमएलए के तहत ईसीआईआर सार्वजनिक नहीं की जाती हैं, जिससे पारदर्शिता और उचित प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं।
- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का अतिक्रमण: ईडी के पास गिरफ्तारी और संपत्ति कुर्की के व्यापक अधिकार हैं, जिनका प्रयोग कभी-कभी पर्याप्त न्यायिक जाँच के बिना भी किया जाता है।

मौजूदा उपाय और वैश्विक समन्वय

कानूनी एवं संस्थागत ढाँचा

- पीएमएलए, 2002: भारत का प्रमुख धन शोधन विरोधी कानून।
- प्रवर्तन निदेशालय: धन शोधन और विदेशी मुद्रा उल्लंघनों की जाँच करता है।
- **सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय:**

  o पी. चिदंबरम बनाम ईडी (2019): धन शोधन के गंभीर आर्थिक प्रभाव को बरकरार रखा।

  o विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ (2022): स्पष्ट किया कि बिना किसी आपराधिक मामले के संपत्ति कुर्क की जा सकती है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

- एफएटीएफ की सिफ़ारिशें: भारत धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्तपोषण पर वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के दिशानिर्देशों के प्रति प्रतिबद्ध है।
- दोहरे कराधान से बचाव समझौते (डीटीएए): 85 से अधिक देशों के साथ हस्ताक्षरित, डीटीएए वित्तीय और कर-संबंधी डेटा के आदान-प्रदान में सहायता करते हैं, जिससे कर चोरी और अवैध धन हस्तांतरण पर अंकुश लगाने में मदद मिलती है।
- सूचना संलयन केंद्र-हिंद महासागर क्षेत्र: क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से समुद्री सुरक्षा और संदिग्ध लेनदेन पर नज़र रखने को बढ़ाता है।

आगे की राह

- भारत में धन शोधन से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, निम्नलिखित कदम आवश्यक हैं:

1. प्रवर्तन निदेशालय की जाँच में पारदर्शिता और उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करें; ईसीआईआर को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए।
2. बेहतर केस तैयारी, वित्तीय जाँचकर्ताओं के प्रशिक्षण और अभियोजन प्रक्रिया को मज़बूत करके दोषसिद्धि दर में सुधार करें।
3. यह सुनिश्चित करके राजनीतिक दुरुपयोग से बचें कि प्रवर्तन निदेशालय का कामकाज स्वतंत्र रहे और संसदीय निगरानी के अधीन रहे।
4. डीटीएए, एफएटीसीए और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग तंत्रों के माध्यम से प्रौद्योगिकी और डेटा साझाकरण का उपयोग करें।
5. एफएटीएफ की सिफारिशों को सख्ती से लागू करें, विशेष रूप से लाभकारी स्वामित्व, सीमा पार डेटा विनिमय और गैर-वित्तीय क्षेत्रों की निगरानी पर।

निष्कर्ष

- मनी लॉन्ड्रिंग केवल एक वित्तीय अपराध नहीं है—यह आतंकवाद के वित्तपोषण, भ्रष्टाचार और कर चोरी को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय सुरक्षा को कमज़ोर करता है। हालाँकि भारत ने एक मज़बूत कानूनी और संस्थागत ढाँचा बनाया है, लेकिन कार्यान्वयन में कमियाँ, प्रवर्तन तंत्र का दुरुपयोग और कमज़ोर दोषसिद्धि दर इसकी प्रभावशीलता को कमज़ोर करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है—ऐसा दृष्टिकोण जो प्रवर्तन को मज़बूत करे, साथ ही कानून के शासन को बनाए रखने और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा के लिए जवाबदेही, पारदर्शिता और न्यायिक निगरानी भी सुनिश्चित करे।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या में न्यायपालिका की भूमिका पर चर्चा कीजिए। न्यायिक हस्तक्षेप ने इसके कार्यान्वयन को किस प्रकार आकार दिया है?

Page 11 : GS 2 : Governance

आधुनिक लोकतंत्रों में, जहाँ मानवाधिकार और सम्मान स्पष्ट रूप से आधारभूत हैं, किन लोगों के जीवन की रक्षा की जाए और किनकी मृत्यु को सामान्य माना जाए, इस बारे में व्याप्त घोर असमानता एक गहरी और चिंताजनक अंतर्धारा को उजागर करती है - नेक्रोपॉलिटिक्स। कैमरून के दार्शनिक अकिल एमबेम्बे द्वारा गढ़ा गया, नेक्रोपॉलिटिक्स राजनीतिक शक्ति के प्रयोग को यह तय करने के लिए संदर्भित करता है कि कौन जीवित रहेगा और किसे मरना होगा। यह आलोचना करता है कि कैसे राज्य, संस्थाएँ और व्यवस्थाएँ हाशिए पर पड़ी आबादी को मृत्यु, हिंसा या परित्याग के लिए दुर्घटना के रूप में नहीं, बल्कि नीति और सत्ता संरचनाओं के जानबूझकर किए गए परिणामों के रूप में उजागर करती हैं।

Necropolitics: who is allowed to live and who may die

Necropolitics is a theory that examines how modern nation states determine whose lives are disposable and may be sacrificed in the name of security, threat, or political control

Rebecca Rose Varghese

Have you ever noticed how an airstrike in Mumbai triggers national outrage, but a similar attack in Kashmir rarely breaks through the noise? We're so accustomed to hearing about violence there that it barely feels like news. It's as if deaths in these regions are already anticipated and normalised. These aren't just accidents of geography. They are symptoms of a deeper system, a politics that decides whose lives are worth grieving and whose deaths are simply part of the landscape.

Necropolitics is the use of political power to determine who is allowed to live and who can be made to die. It describes how states and institutions manage death by exposing certain populations, such as refugees, the poor, or racialised communities, to violence, abandonment, or structural neglect.

Coined by Cameroonian historian Achille Mbembe in a 2003 essay and later expanded in his book *Necropolitics* (2019), the concept builds on Michel Foucault's notion of biopolitics but shifts the focus. While biopolitics is concerned with managing life and populations, necropolitics interrogates the power to let people die, deciding who is disposable, who may be sacrificed, and whose suffering is structurally ignored.

Sanctioned death: A man who was shot while seeking food aid at an Israeli and U.S.-backed distribution point, is carried on a motorcycle in the central Gaza Strip on July 27. AFP

Biopolitics versus necropolitics

Foucault traces how the organisation of power changed over time: from sovereign power, where rulers exercised authority through public spectacles of death, to disciplinary power, which works through institutions like schools and prisons to train individuals using surveillance and routine. This evolved into biopower – the control of entire populations through the optimisation of life via vaccination, sanitation, census-taking, and reproductive governance. Biopower appears progressive, but as Foucault warned, it carries within it the power to "make live and let die."

Mbembe takes this further. He asks: if biopolitics is truly about preserving life, why are so many still dying? Why are certain lives treated as expendable? Biopolitics tells only half the story. The other half is necropolitics, the deliberate exposure of certain populations to death, not by accident but by design. While biopolitics governs life, necropolitics governs death. It does not merely ignore suffering; it produces it with calculated precision. Necropolitics is not about letting people die, but about making them die.

Unlike sovereign power, necropolitics does not rely on the will of a single ruler. It operates through policies, institutions, and global indifference that erases the value of some lives. These lives are stripped of dignity, reduced to statistics, and rendered disposable. This logic, Mbembe argues, has deep colonial roots. Consider the Bengal famine of 1943. Millions died not due to a lack of food, but because British colonial policies prioritised imperial interests over Indian lives. Death was systemic, not accidental. People were treated as tools for the empire, valued only in relation to others' survival.

In necropolitical systems, people are not killed through spectacle but through slow, structural abandonment. Death is normalised and bodies become data. The people, whether in borders, refugee camps, or detention centres, are managed, contained, and forgotten. For instance, during the HIV/AIDS crisis of the 1980s and '90s, queer people, especially Black, brown, trans, and working-class individuals, were abandoned by healthcare systems and denied dignity. As scholars like Judith Butler and Jasbir Puar note, only queer lives made respectable through whiteness or middle-class identity were grieved.

Puar calls this queer necropolitics, where some queer lives are protected while others are left to die.

Characteristics of necropolitics

Necropolitics operates through several defining features that together create a system where certain lives are systematically devalued. First, state terror suppresses dissent through surveillance, violence, imprisonment, or elimination, even within democracies. Second, states collaborate with private militias or criminal groups, blurring the line between state and non-state violence. Third, enmity becomes a governing principle, making the right to kill a measure of authority. Fourth, war and terror become self-sustaining economies, fuelling global surveillance and arms markets. Fifth, active predation of certain social groups displaces entire communities, as seen in resource extraction projects. Sixth, death is administered in varied forms like torture, drone strikes, starvation, and disappearance. Finally, these acts are morally justified through ideologies like nationalism, religion, or utilitarianism.

Creating a state of exception

Necropolitics is sustained not only through violence but through the systematic invention of enemies. Modern states are driven by the desire for an enemy onto whom fear and blame can be projected. This enemy need not be real – the fantasy alone justifies surveillance, exclusion, and elimination. In neoliberal regimes, the threat turns inward, prompting expanded policing and emergency laws that target not just the accused but also those who resemble them.

Italian philosopher Giorgio Agamben calls this condition the state of exception, when the law suspends itself in the name of preserving itself. Mbembe expands this to show how, for many populations, the exception is not temporary but permanent.

In such spaces, legality becomes hollow and rights are applied selectively. What governs is not justice but logistics, such as who gets care, who receives compensation, who can cross a border, and who is punished for trying. These decisions may seem administrative, but they are deeply necropolitical, revealing how life and death are unequally distributed.

The living dead

Mbembe also introduces a haunting concept within necropolitical thought – the living dead: people who are not killed outright but are forced to live in conditions so degraded, unstable, and violent that life becomes a slow, continuous dying. These are individuals and communities who may remain biologically alive but are stripped of political, social, and moral recognition.

We saw this during India's COVID-19 lockdown, when migrant workers were left to walk for days without food, shelter, or transport. Many collapsed and died on highways or railway tracks, not from the virus, but from state neglect. Their deaths were quietly processed and bureaucratically explained and largely unmourned.

Mbembe calls these zones death worlds – spaces where populations are exposed to abandonment or sudden violence. Drawing from Agamben's "state of exception," Mbembe shows how these spaces operate outside the usual rule of law. Here, death is not a breakdown of governance but its very method.

Gaza is one of the starkest examples. After the Hamas attack on October 7, 2023, Israeli strikes flattened hospitals, aid centres, and homes. Even the deaths of children were dismissed as collateral damage. The silence that followed reveals necropolitics at its clearest: some deaths are not just permitted but framed as necessary for political strategy and national security.

In everyday life

Necropolitics does not always come with bombs or guns. More often, it takes the form of law, policy, and bureaucracy – sterilisation drives targeting Dalit and Adivasi women, police databases that profile Muslim names or Black people, drone strikes that label civilians as "targets," or detention centres where children sleep on cold floors. These are not failures of a protective system, but features of one designed to discard.

It also exists in silence – in the world, including states and global institutions – looking away as thousands of civilians, including women and children, are killed in places like Gaza, while the rest of us carry on with our daily lives. Necropolitics is not confined to war zones. It thrives in the slow violence of poverty, caste, racism, and displacement.

So, if power today functions through abandonment and death, what does resistance look like? The goal must not simply be to survive, but to live lives that are recognised, valued, and grieved.

Rebecca Rose Varghese is a freelance journalist.

अवधारणा को समझना

- बायोपॉलिटिक्स से नेक्रोपॉलिटिक्स तक: मिशेल फूको की बायोपॉलिटिक्स स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता और जनसांख्यिकी के माध्यम से जनसंख्या के नियमन और जीवन प्रबंधन पर केंद्रित थी। एमबेम्बे इसे नेक्रोपॉलिटिक्स तक विस्तारित करते हैं, जहाँ राज्य न केवल जीवन का प्रबंधन करता है, बल्कि सक्रिय रूप से तेज़ (युद्ध, हिंसा) और धीमी (संरचनात्मक उपेक्षा) दोनों तरह से मृत्यु उत्पन्न करता है।
- शासन के रूप में मृत्यु: नेक्रोपॉलिटिक्स में, मृत्यु व्यवस्था की विफलता नहीं है, बल्कि इसका तरीका है जो गाजा जैसे युद्ध क्षेत्रों, भारत में जाति-आधारित उपेक्षा और कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान कमजोर समूहों के परित्याग में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

समकालीन संदर्भ में उदाहरण

1. कोविड-19 के दौरान भारत के प्रवासी श्रमिक: 2020 के लॉकडाउन ने प्रवासी श्रमिकों के प्रति संरचनात्मक उदासीनता को उजागर किया, जिनमें से कई लोग घर वापस जाते समय मर गए, वे वायरस के नहीं बल्कि राज्य की उपेक्षा के शिकार हुए - यह मृतप्राय राजनीति का एक पाठ्यपुस्तकीय मामला है।

2. कश्मीर या गाजा जैसे संघर्ष क्षेत्र: हिंसा का अनुपातहीन सामान्यीकरण, निरंतर आक्रोश का अभाव और चुनिंदा शोक यह दर्शाते हैं कि कैसे कुछ भौगोलिक क्षेत्रों को मृत्युलोक माना जाता है, जहाँ जीवन नगण्य है।

3. दलित/आदिवासी महिलाओं की नसबंदी और डिजिटल प्रोफाइलिंग के माध्यम से मुसलमानों की निगरानी, ऐसी संस्थागत प्रथाएँ हैं जो समुदायों को शक्तिहीन और अवमूल्यित करती हैं, और नौकरशाही के माध्यम से मृत-राजनीति को प्रदर्शित करती हैं।

4. नागरिकों की मृत्यु पर वैश्विक चुप्पी: यमन से लेकर गाजा तक, मानवीय संकटों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मौन प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि कैसे भू-राजनीतिक हित मानव जीवन के मूल्य पर हावी हो जाते हैं।

नैतिक और संवैधानिक आयाम

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार की गारंटी देता है, फिर भी मृत-राजनीतिक शासन संसाधनों, न्याय और मान्यता तक असमान पहुँच के माध्यम से इसका उल्लंघन करता है।
- राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (DPSP) सामाजिक और आर्थिक न्याय पर ज़ोर देते हैं, लेकिन जब गरीबी, जाति, धर्म और नस्ल का इस्तेमाल चुनिंदा कानूनों को लागू करने या देखभाल से इनकार करने के लिए किया जाता है, तो नेक्रोपॉलिटिक्स फलती-फूलती है।
- नैतिक दृष्टिकोण से, नेक्रोपॉलिटिक्स कांट के उस सिद्धांत का खंडन करती है जिसमें व्यक्ति को साधन नहीं, बल्कि साध्य माना जाता है, और यह नैतिक शासन के प्रमुख सिद्धांतों, करुणा, समता और गरिमा की अवहेलना करती है।

निष्कर्ष

- नेक्रोपॉलिटिक्स लोकतंत्र के मूल ढांचे को चुनौती देती है, यह उजागर करती है कि कैसे शासन समावेशन के बजाय परित्याग का साधन बन सकता है। इस अदृश्य हिंसा को पहचानना प्रतिरोध की दिशा में पहला कदम है। सच्चे शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी जीवन त्याज्य न हो, और गरिमा, देखभाल और न्याय कुछ लोगों के लिए विशेषाधिकार न हों, बल्कि सभी के अधिकार हों। एक ऐसी दुनिया में जो इस बात को लेकर लगातार विभाजित होती जा रही है कि कौन मायने रखता है और कौन नहीं, आह्वान केवल जीवित रहने का नहीं है, बल्कि ऐसा जीवन जीने का है जो दृश्यमान हो, मूल्यवान हो, और जिसके खोने पर शोक मनाया जाए।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: जाति, वर्ग और सांप्रदायिक पहचान भारत में 'मृत्यु लोक' के निर्माण को कैसे प्रभावित करती हैं? नेक्रोपॉलिटिक्स की अवधारणा के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। **(150 words)**

Page : 08 Editorial Analysis

The technocratic calculus of India's welfare state

Anmol Rattan Singh

is the Co-founder of the PANJ Foundation, a Punjab-based policy research think tank

Agastya Shukla

is a Programme Associate at the PANJ Foundation, a Punjab-based policy research think tank

With a billion Aadhaar enrollments, 1,206 schemes integrated into the Direct Benefit Transfer system, and 36 grievance portals across States/Union Territories, India's welfare orientation is transitioning into a technocratic calculus. The promise to deliver social welfare at scale, bypassing leaky pipelines and eliminating ghost beneficiaries, might have led to a 're-casting' that delivers 'efficiency' and 'coverage' at the cost of 'democratic norms' and 'political accountability'.

An offloading

Are we witnessing the emergence of a post-rights based welfare regime? Is the Indian digital welfare state headed towards a systemic impasse? What is the technocratic calculus behind all this? Recent game-theoretic work shows that technocratic rule thrives where parties are polarised. Evidently, our questions have changed. We have shifted from "who deserves support and why?" to "how do we minimise leakage and maximise coverage?" Our politicians across party lines have rationally offloaded hard-choices onto data-driven algorithms without questioning the complexities of constitutional values.

Contextualising Habermas's 'technocratic consciousness' and Foucault's 'governmentality', India's welfare architecture is increasingly shaped by measurable, auditable, and depoliticised rationality. Schemes such as E-SHRAM and PM KISAN embody a uni-directional, innovation-led logic that is streamlined, measurable, and intolerant of ambiguity or error. Conversely, we have deliberative calls for participatory planning and local feedback embodying the long forgotten core of democratic thinking resonating Giorgio Agamben's notion of homo sacer – a life stripped of political agency.

Seemingly, welfare, in the contemporary context, has ceased to exist as a site of democratic deliberations. On a microscopic level, a rights-bearing citizen has been replaced by the auditable beneficiary. Thus, it calls for an urgent need for the state to revisit (in a Rancierean sense) whether it is curating who is visible, who can complain, and whose suffering is computable. Despite claims of a 'socialistic state', we observe a decade-low decline in India's social sector spending that has dwindled to 17% in 2024-25 from the 2014-24 average of 21%. Further, there are some interesting observations beyond plain statistics. Key social sector schemes have borne the brunt of such decline where minorities, labour, employment, nutrition and social security welfare saw a significant decline from 11% (in the pre-COVID-19 phase) to 3% (in post-COVID-19 phase).

> The promise to deliver social welfare at scale, using data-driven algorithms, may be at the cost of 'democratic norms' and 'political accountability'

Parallely, social commentators often comment the Right to Information (RTI) regime to be in 'existential crisis' and further uncovering the cloak on RTI exposes a critical issue within the institution of dysfunctional information commissions. As of June 30, 2024, the number of pending cases crossed the four lakh tally across 29 Information Commission's (ICs), and eight CIC posts were vacant (annual report of CIC, 2023-24).

The Indian welfare regime must recover its capacity for reflexivity and situated knowledge, elements that are very peculiar to gram sabhas and frontline bureaucratic discretions. To draw Rancière's critique on democracy, we highlight one major impending concern, that "democracy depends on whose suffering is rendered visible and contestable, not merely computable". This concern is further highlighted in Justice D.Y Chandrachud's Aadhaar dissent (2018), that warned precisely against such decontextualisation of identity which served as a caution against reducing citizens to disembedded, machinic data who are devoid of care, context, or even constitutional assurance in some cases.

Another instance of algorithmic insulation

Another worrisome trend is the Centralised Public Grievance Redress and Monitoring System's flattening of the federal hierarchies into ticket-tracking systems. Although it is a novel initiative resolving tickets and routing complaints across state agencies, empirical data show that lakhs of grievances were disposed of between 2022-24. But on a closer examination it might just be centralising the visibility but not the responsibility – a form of algorithmic insulation that renders political accountability increasingly elusive.

These observations are not to dismiss the value of such initiatives. Rather, they invite a deeper conversation on how welfare governance can evolve for a more resilient and responsive state. The government should now think along the lines of 'democratic antifragility' so that our systems built on perfect data and flawless infrastructure do not fail catastrophically under stress (consider Taleb's 'hyper-integrated systems').

We need to empower States to design context-sensitive regimes where federalism and welfare push for pluralism as a feature. Institutionalising community-driven impact audits (as reiterated by the UN Special Rapporteur on Extreme Poverty), by looping in the Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan and Gram Panchayat Development Plans should be the core target. All States must be made capable to build platform cooperatives where self-help groups act as intermediaries; functionally, lessons can be learnt from Kerala's Kudumbashree. Civil society must be incentivised to invest in grass-roots political education and legal aid clinics in order to strengthen the community accountability mechanisms. Lastly, it is time we strengthen and codify our offline fall-back mechanisms, human feedback safeguards, and statutory bias audits by embedding the "right to explanation and appeal" – as proposed by the UN Human Rights for digital governance systems.

Focus on the citizen

We, as citizens of India, must realise that a welfare state stripped of democratic deliberations is a machine that works efficiently for everyone except those it is meant to help. For a Viksit Bharat we will have to reorient digitisation with democratic and anti-fragile principles so that citizens become partners in governance, and not mere entries in a ledger.

GS. Paper 02 शासन

UPSC Mains Practice Question: भारत की कल्याणकारी व्यवस्थाएँ तकनीकी तर्क से प्रेरित होती जा रही हैं, और अक्सर लोकतांत्रिक विचार-विमर्श की कीमत पर। भारत में विकसित हो रहे डिजिटल शासन ढाँचे के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। **(250 words)**

संदर्भ:

पिछले एक दशक में भारत के कल्याणकारी ढाँचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली में 1,200 से अधिक योजनाओं के एकीकृत होने और लगभग एक अरब आधार नामांकन के साथ, राज्य कुशलतापूर्वक कल्याण प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित शासन पर तेज़ी से निर्भर हो रहा है। हालाँकि, यह तकनीकी बदलाव, कवरेज और लीक-प्रूफ़ सिस्टम सुनिश्चित करते हुए, लोकतांत्रिक जवाबदेही, राजनीतिक एजेंसी और अधिकार-आधारित समावेशन पर चिंताएँ पैदा करता है।

मुख्य विश्लेषण:

1. तकनीकी गणना बनाम लोकतांत्रिक विचार-विमर्श:

- पीएम-किसान और ई-श्रम जैसी कल्याणकारी योजनाएँ सामुदायिक भागीदारी या अधिकार-आधारित पात्रता के बजाय मापनीय परिणामों, लेखापरीक्षा और एल्गोरिथम नियंत्रण के तर्क द्वारा निर्देशित होती हैं।
- ध्यान "कल्याण का हकदार कौन है" से हटकर "अक्षमताओं को कैसे दूर किया जाए" पर केंद्रित हो गया है - जो विचार-विमर्श वाली लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से पीछे हटने का संकेत देता है।

2. एल्गोरिथम शासन और बहिष्करण:

- नागरिकों को अधिकार-धारक व्यक्तियों के बजाय डेटा बिंदुओं के रूप में देखा जा रहा है - जो हैबरमास की तकनीकी चेतना और फूको की शासनात्मकता की प्रतिध्वनि है।
- आधार फैसले (2018) में न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की असहमति ने इस तरह के अमानवीयकरण के विरुद्ध चेतावनी दी, और उन पहचान प्रणालियों के प्रति आगाह किया जो व्यक्तियों को संदर्भ या देखभाल से रहित मशीनी रिकॉर्ड में बदल देती हैं।

3. सामाजिक क्षेत्र के खर्च में कमी:

- सामाजिक क्षेत्र का व्यय 2024-25 में घटकर 17% रह गया है, जबकि पिछले दशक में यह औसतन 21% था, जिससे अल्पसंख्यक, श्रम और पोषण जैसे संवेदनशील क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं।
- यह राज्य की प्राथमिकताओं और जमीनी स्तर की ज़रूरतों के बीच एक विच्छेद को दर्शाता है, जो समाजवादी लोकाचार (अनुच्छेद 38, डीपीएसपी) के प्रति राज्य की घोषित प्रतिबद्धता के विपरीत है।

4. शिकायत निवारण और आरटीआई व्यवस्था में संकट:

- केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस), कुशल होने के बावजूद, स्थानीय जवाबदेही सुनिश्चित किए बिना आंकड़ों को केंद्रीकृत कर देती है।
- 4 लाख से अधिक आरटीआई मामले लंबित होने और सूचना आयोगों में रिक्तियों के कारण, लोकतांत्रिक कल्याण का एक प्रमुख स्तंभ पारदर्शिता कमजोर हो रही है।

5. संवेदनशीलता और सहभागी शासन की आवश्यकता:

- कल्याण को केंद्रीकृत, एक ही तरह के सभी के लिए उपयुक्त मॉडल से आगे बढ़ना होगा। केरल के कुदुम्बश्री से सबक लिया जा सकता है, जहाँ स्वयं सहायता समूह कल्याण वितरण में मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं।
- ग्राम सभाओं, जीपीडीपी और समुदाय-आधारित लेखा परीक्षा जैसी संस्थाओं को नीचे से ऊपर तक जवाबदेही बहाल करने के लिए सशक्त बनाया जाना चाहिए।

आगे की राह:

- मानवीय निगरानी और उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल कल्याण प्रणालियों में "स्पष्टीकरण का अधिकार" शामिल करें।
- नागरिक समाज को ज़मीनी स्तर पर राजनीतिक शिक्षा और कानूनी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करें।
- कल्याण एल्गोरिदम के डिजिटल बहिष्करण और वैधानिक पूर्वाग्रह ऑडिट के लिए 'ऑफ़लाइन फ़ॉलबैक तंत्र' बनाएँ।
- कल्याणकारी नीति डिज़ाइन में संघीय बहुलवाद सुनिश्चित करें जो संदर्भ-संवेदनशील और क्षेत्रीय रूप से अनुकूल हो।

निष्कर्ष:

- जैसे-जैसे भारत एक विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है, ज़रूरत सिर्फ़ कुशल प्रणालियों की नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण प्रणालियों की भी है। एक कल्याणकारी राज्य को, अपनी सच्ची भावना के अनुरूप, अपने नागरिकों की स्वतंत्रता, सम्मान और आवाज़ की रक्षा करनी चाहिए, न कि उन्हें एक तकनीकी मशीन के अदृश्य पुर्ज़ों में बदल देना चाहिए। एक कल्याणकारी व्यवस्था का असली पैमाना सिर्फ़ कवरेज के आँकड़ों में नहीं, बल्कि इस बात में निहित है कि क्या वह ज़रूरतमंदों की देखभाल, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ सेवा करती है।